



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

12-1787

सं. 110]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 1989/फाल्गुन 12, 1910

No. 110]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 1989/PHALGUNA 12, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1989

का प्रा 173(अ) — बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 क खण्ड (यख) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने के बाद अंतर्कनगर माजिबडे नगरी सहकारी बैंक लि., ठाणे (जिसे इसके पश्चात् "सहकारी बैंक" कहा गया है) के संबंध में एनद्द्वारा 3 मार्च 1989 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर, 2 मिनम्बर 1989 तक और उस दिन को मिलाकर अधिव्यगन आदेश जारी करना है जिसके अनुसार अधिव्यगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कारुवाइयो का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गयी कारुवाइयो को जारी रखना स्वगित किया जाता है किन्तु नर्त यह है कि इस प्रकार के अधिव्यगन का किसी भी प्रकार से माराट्ट को-ऑपरेटिव मायाट्टी अधिनियम 1960 के अंतर्गत

महाराट्ट सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जान वाले उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

2 केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा यह निदेश देती कि स्वीकृत अधिव्यगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की विखित पूर्वानुमति के बिना कोई अणु अथवा अधिम नहीं देगा, किसी अधिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिमम्पति का अणु गकामण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का रायिस्थ स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अणु रायिस्था और देनदारियों के संबंध में अथवा अणुया किसी प्रकार की अणुयागो नहीं करेगा अथवा अणुयागी करता स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का गमसीता अथवा ठहराव नहा करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अणुयागिया अथवा खच करेगा —

(1) प्रत्येक वचन बैंक अणुया काटू या अथवा किसी भी नाम से पुकार जाने वाले किसी अणुया जमा खाने में शेष रकम से से 50 तक —

वणत कि अणुया को गयी रकम की कुल माया रिमी ए 6 अणुया (किसी अणुया व्यसित के साथ सयुक्त खाने में नहा) के नाम में खाने में जमा अणुया गणित 50 स्पण में ज्यादा न हो,

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अथवा नहीं की जायगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्तृदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट पे आदेश अथवा चेक की राशि जो सहकारी बैंक द्वारा उस तारीख का जारी कर दिए गये है जितना उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है जिसको अधिव्यक्त आदेश लागू होता है

(3) 3 मार्च 1939 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त दृष्टियों का भुगतान चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हों

(4) ऐसा कोई व्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा उसके अथवा उसके ब्रिद्ध दावर किए गए मुकद्दम, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके ब्रिद्ध को गये दंडों या बैंक का मिलने वाली किसी रकम का वसूल करने के समय में किया आवश्यक है वगैरे कि प्रत्येक मुकद्दम, अपील अथवा ब्रिद्ध के तब से किए जाने वाले व्यय की रकम 500 रुपये से अधिक है ता खर्च करने में वहन मार्गाय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जायगी

(5) ऐसा कोई व्यय जो निवेश बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी का देय प्रीमियम की राशि हो, और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के बिहार से बैंक का दैनिक प्रणमत चलाने के लिए करना अनिवार्य हो

अर्थात् कि जहां किसी एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिव्यक्त आदेश से पहले के छः कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बड़ा जाता हो अथवा उस अवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किशो जाने बाधा व्यय 250 रुपये से बड़ा जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व मास्रीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप से अनुमति ली जायगी।

3. कर्नाटक सरकार एतद्द्वारा यह भी निर्देश देती है कि सहकारी बैंक की स्वीकृत अधिव्यक्त की अवधि के दौरान —

(क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगिया कर सकेगा अर्थात् सरकारी प्रतिभूतिया अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार अथवा महाराष्ट्र स्टेट का-ऑपरेटिव एक्स बैंक लि या ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का-ऑप बैंक लि, ठाणे अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक का किए गए ऋण अथवा अधिमो, जो अधिव्यक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख या चूकाए जाने से 4, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हो।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वाभित अदायगिया करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट का-ऑपरेटिव एक्स बैंक लि अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खान चलाने की अनुमति दी जायगी।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के लिए जान से पहले महाराष्ट्र स्टेट का-ऑपरेटिव एक्स बैंक लि अथवा ऐसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपकी प्राप्ति करना होगा कि इस आदेश द्वारा धरायी गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक उन दंडों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर सीटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन दंडों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसी दंडों में उसका कोई हित न हो।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे साल अथवा प्रतिभूतिया का जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण, नकद, कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि बंधक अथवा बंधक रखी गयी हो, अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हों, निम्नलिखित मामला में छोड़कर अथवा दे सकेगा —

(1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋणकर्ताओं में मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गयी है, और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा सभव हो, निश्चित अनुपातों में नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिव्यक्त आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थीं, इनमें जा भी ऊर्ध्व हों, उक्त मान और प्रतिभूतिया पर माजिन के अनुपातों को कम किये बिना।

[स. 6-1/89- एसी]

पी. क. नयान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1989

S.O. 173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (2b) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Vartaknagar-Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd., Thane (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 3rd March, 1989 upto and inclusive of the 2nd September, 1989 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 50 :

Provided that the total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the

name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 50 :

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before 3rd March, 1989 whether realized before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it :

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

- (v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that, during the period of the moratorium granted to the Co-operative Bank—

- (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying

loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Thane District Central Co-operative Bank Ltd.; or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

- (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid :

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;
- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—
 - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and
 - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportion of the margins on the said goods, or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 6—1/89-AC]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

